

My Notes.....

राष्ट्रीय

अधूरा रह गया 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य'

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में धरती से गरीबी मिटाने का जो सपना दुनियाभर के नेताओं ने देखा था वह अधूरा रह गया है। खास कर भारत में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के लिए 2015 तक जो दर्जनभर टारगेट तय किए गए थे उनमें से बमुश्किल आधे ही पूरे हुए हैं। यह अहम खुलासा सरकार की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट-

अचीविंग मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स :

1. टारगेट ईयर फैक्टशीट-इंडिया से पता चलता है कि आठ लक्ष्यों (एमडीजी) के 18 टारगेट में से भारत के संबंध में सिर्फ 12 टारगेट महत्वपूर्ण थे जिनमें से महज छह ही पूरे हुए हैं।
2. देश को ये टारगेट 2015 तक पूरे करने थे। रिपोर्ट के अनुसार भूखमरी और अत्यंत गरीबी को मिटाने के लक्ष्य के संबंध में एक डालर प्रतिदिन से गुजारा करने वाले लोगों की संख्या 2015 तक आधी करने का लक्ष्य पाने में भारत कामयाब रहा है लेकिन भूखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या घटाकर आधी करने के लक्ष्य से अभी कोसों दूर है।
3. इसी तरह सबको प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य भी अभी हासिल नहीं हुआ है। वैसे शिक्षा के मामले में असमानताएं दूर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
4. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर दो-तिहाई घटाने का लक्ष्य भी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। मातृत्व मृत्यु दर में 1990 से 2015 तक तीन चौथाई कमी करने का लक्ष्य भी अभी हासिल नहीं किया गया है।
5. वैसे एचआइवी एड्स पर अंकुश लगाने तथा मलेरिया और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण करने के मामले में देश ने असफलता हासिल की है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के मामले में तीन टारगेट में से सिर्फ एक को ही पूरा किया गया है। वैसे निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी खासकर सूचना और संचार तकनीक का फायदा लोगों तक पहुंचाने का टारगेट हासिल कर लिया गया है।
6. उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर 2000 को हुए संयुक्त राष्ट्र के एमडीजी पर 189 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। हर देश को 2015 तक इन लक्ष्यों को हासिल करना था। हालांकि ये लक्ष्य हासिल न होते देख संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में एक बार सतत विकास लक्ष्य तय किए हैं। सभी देशों को इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है।

ये थे आठ सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

1. भूखमरी और अत्यंत गरीबी को मिटाना
2. सबको प्राथमिक शिक्षा
3. लैंगिंग समानता और महिला सशक्तिकरण
4. बाल मृत्यु दर घटाना
5. जननी स्वास्थ्य सुधार
6. एचआइवी, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना
7. पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना
8. विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना।

क्योटो समझौते का दूसरा दौर लागू करेगा भारत

भारत ने पर्यावरण सुधार के अपने वादे पर आगे बढ़ते हुए क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे दौर के नियमों को लागू करने को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैसों की मात्रा में और कटौती की जानी है। क्या है

1. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इस बाबत जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर दोहा संशोधन पर अपनी योजना के मसौदे को भारत ने दाखिल कर दिया है।
2. इसी के साथ समझौते के दूसरे दौर को स्वीकार करने वाला भारत 80वां देश बन गया है। भारतीय मिशन ने कहा कि हमारा यह निर्णय भारत की पर्यावरण सुधार के प्रति मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

3. मसौदे को दाखिल करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया- पर्यावरण सुधार के लिए भारत के प्रयास जारी हैं।
4. संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे में पर्यावरण सुधार के लिए हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते को क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है।
5. यह वातावरण में हानिकारक गैसों को उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के संकल्प और उसके प्रयासों को इंगित करता है।
6. इसे जापान के क्योटो शहर में हुए सम्मेलन में दिसंबर 1997 में स्वीकार किया गया था, जबकि फरवरी 2005 में यह लागू हुआ।

गाद की समस्या पर समिति

सरकार ने स्वीकार किया कि गंगा में भारी मात्रा में गाद जमा होना एक बड़ी चुनौती है और सरकार बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों एवं केंद्र की सहभागिता वाली एक समिति जल्द बनाने जा रही है ताकि गाद की समस्या को दूर किया जा सके। लोकसभा में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, अधीर रंजन चौधरी आदि के पूरक प्रश्नों के उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह सच्चाई है कि गंगा नदी में गाद एक बड़ी समस्या है।

क्या है

1. इस संबंध में साल 2002 में मित्तल समिति का गठन किया गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट धूल खाती रही। हमने माधव चिताले समिति बनाई और उसने रिपोर्ट पेश की। हमने इस रिपोर्ट को बिहार सरकार को दिखाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में कुछ सुझाव भी दिए।
2. भारत में पहले परंपरा थी कि केवट, निषाद, धीमर समुदाय के लोग मानसून के बाद रेत की मूर्तियां बनाते थे और बाद में रेत निकालकर लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन समय के साथ नदी में रेत पर रेत माफिया का कब्जा हो गया। ऐसे में इन समुदायों के हाथ से रेत का काम चला गया।
3. सरकार बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों एवं केंद्र की सहभागिता वाली एक समिति जल्द बनाने जा रही है ताकि फरक्का समेत अन्य स्थानों पर गाद की समस्या को राज्यों के सहयोग से दूर किया जा सके।

यूपी ने हासिल किया नीति आयोग का 'साथ'

बदहाल शिक्षा और खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बीमारू राज्यों में जोरदार ललक दिखी है। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने यहां इन सुविधाओं को सुधारने के लिए बाकी प्रदेशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में नीति आयोग का साथ हासिल करने में सफलता हासिल की है। दरअसल साथ (एसएटीएच) का मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के लिए नीति आयोग की एक पहल है। इसके तहत आयोग राज्यों को अलग-अलग तरह से मदद मुहैया कराता है। जिन राज्यों को मदद मुहैया कराई जानी है उनका चयन सभी प्रदेशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद किया गया है।

क्या है

1. आयोग के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए 'साथ' कार्यक्रम के तहत सिर्फ तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का चयन किया गया है।
2. जबकि शिक्षा के क्षेत्र में का करने के लिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड का चयन किया गया है। इन छह प्रदेशों का चयन लंबे समय तक चली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।
3. नीति आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आयोग राज्यों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर आयोग के समक्ष प्रजेंटेशन दिए। आयोग की एक चयन समिति ने इन प्रस्तावों का परीक्षण किया जिसके बाद इन छह प्रदेशों का नाम चुना गया है।
4. इस अनूठी पहल के तहत नीति आयोग अगले तीन साल तक इन राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए मदद करेगा ताकि इनकी सफलता के मॉडल को दूसरे प्रदेशों में अपनाया जा सके।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के सर्विस डिलीवरी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि इस अभियान में राज्य सरकार, नीति आयोग के अलावा एक नॉलेज पार्टनर भी होगा।
6. अधिकारी ने कहा कि 'साथ' कार्यक्रम सहकारी संघवाद के मॉडल का जीता जागता उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि हाल में नीति आयोग ने राज्यों के साथ मिलकर उनके विकास कार्यक्रम बनाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी तरह का एक प्रयास आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ भी किया है।

नौकरशाहों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली

एक संसदीय समिति ने सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को भी सेना द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया की तर्ज पर रखने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर के नौकरशाहों की नियुक्ति के लिए तैयार की गई नई 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को और पारदर्शी और नियम आधारित बनाया जाना चाहिए।

क्या है

1. संसदीय समिति ने विभिन्न भागीदारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का उल्लेख किया है। भागीदारों ने कहा है कि केंद्रीय अधिकारी योजना के तहत होने वाला मनोनयन सभी भागीदार सेवाओं को समान अवसर मुहैया नहीं कराता है। खास तौर से गैर आइएएस सेवाओं के मामले में यह देखा जा सकता है।
2. भारत सरकार के तहत संयुक्त सचिव और ऊपरी स्तर के पदों के लिए मनोनयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल सभी संस्थान या निकाय में एक ही सेवा आइएएस अधिकारियों का दबदबा रहता है।
3. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे रखा है। समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की जा चुकी है।

इंडिया रिटायरमेंट में सबसे खराब देश

43 देशों के ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स (जीआरआई) में भारत को सबसे निचला स्थान हासिल हुआ है। फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी नैटिक्सस की ओर से तैयार किया गया इंडेक्स चार फैक्टर के आधार पर देशों को रैंक देता है, जो कि आरामदायक रिटायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ताकि गुणवत्ता वाली वित्तीय सेवाओं तक पहुंच यानी कि बचत मूल्य को संरक्षित करने, अधिकतम आय, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, और एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में मदद की जा सके। इन सभी श्रेणियों में भारत को निचला स्थान हासिल हुआ है। स्विट्जरलैंड, नार्वे और आइसलैंड इसमें अव्वल स्थानों पर रहे हैं।

क्या है

1. फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी नैटिक्सस ग्लोबल की ओर से जारी जीआरआई 2017 के अनुसार, भारत ब्रिक्स देशों में भी रिटायरमेंट के लिए सबसे खराब देश है।
2. पिछले साल भी भारत की रैंकिंग यही थी। भारत को यह रैंकिंग 4 फैक्टर्स (सब-इंडीसीज) के आधार पर मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन चारों मानकों पर भारत की रैंकिंग बॉटम फाइव में है।
3. इस इंडेक्स में 43 देशों की रैंकिंग होती है। इसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) एडवांस्ड इकोनॉमिक्स, ओईसीडी के मेम्बर्स और ब्रिक्स देश (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) शामिल हैं।

'तीव्र मिशन इंद्रधनुष' लांच होगा

पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने और निम्न टीकाकरण कवरेज वाले शहरी क्षेत्रों एवं अन्य इलाकों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 तक लक्ष्य हासिल करने हेतु एक आक्रामक कार्य योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक राज्य 07 अक्टूबर, 2017 से निरंतर चार महीनों तक हर माह की सात तारीख से सात कार्य दिवसों के दौरान तीव्र मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाएगी, जिसमें रविवार, अवकाश दिवस एवं सामान्य टीकाकरण दिवस शामिल नहीं हैं। तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत कुल मिलाकर 118 जिलों, 17 शहरी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों को लक्षित किया जाएगा।

क्या है

1. तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत फोकस नहीं किया जा सका था।
2. शहरी क्षेत्रों में इससे वंचित रही आबादी के मानचित्रण और इन क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाएं मुहैया कराने के लिए एएनएम की आवश्यकता आधारित तैनाती के जरिए यह काम पूरा किया जाएगा।
3. शहरों के इन क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनाती के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवाजाही संबंधी सहायता मुहैया कराई जाएगी।
4. सभी स्तरों पर गहन निगरानी एवं सुदृढ़ जवाबदेही व्यवस्था स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव इस दिशा में हो रही तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे।
5. तीव्र मिशन इंद्रधनुष के लिए चिन्हित प्रत्येक जिले पर संबंधित भागीदार प्रत्येक जिले हेतु चिन्हित मुख्य व्यक्ति के जरिए करीबी नजर रखेंगे।
6. इसके अलावा, तीव्र मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के पूरा हो जाने के बाद तीव्र मिशन इंद्रधनुष के सत्रों को सामान्य टीकाकरण सूक्ष्म योजनाओं के साथ एकीकृत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इन सत्रों के एकीकरण पर संबंधित भागीदार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी करीबी नजर रखेंगे।
7. तीव्र मिशन इंद्रधनुष की एक विशिष्ट खूबी यह है कि इसके तहत अन्य मंत्रालयों/विभागों विशेषकर महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा मामले, एनसीसी इत्यादि से जुड़े मंत्रालयों एवं विभागों के साथ सामंजस्य बैठाने पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
8. भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) का मुख्य उद्देश्य 12 टीका निवारणीय रोगों से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर एवं रुग्णता में कमी लाना है। विगत में यह देखा गया है कि टीकाकरण कवरेज में वृद्धि की गति धीमी पड़ गई थी और वर्ष 2009 एवं वर्ष 2013 के बीच इसमें 1 फीसदी वार्षिक की दर से वृद्धि हुई। इस कवरेज में तेजी लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की गई थी और वर्ष 2015 से इस पर अमल की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज को काफी तेजी से 90 फीसदी के स्तर पर पहुंचाया जा सके।
9. मिशन इंद्रधनुष के चार चरणों को देश के 528 जिलों में पूरा किया जा चुका है। मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक 2.47 करोड़ से ज्यादा बच्चों और लगभग 67 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
10. मिशन इंद्रधनुष के प्रथम दो चरणों के परिणामस्वरूप एक साल में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले इसमें 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई)

भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के हिस्से के रूप में उप-योजना “आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई)” लांच करने का निर्णय लिया है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सेवा संचालन करेंगे। इससे समुदाय की निगरानी में सुरक्षित, किफायती ग्रामीण परिवहन सेवा मिलेगी और महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं (बाजार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य) से दूर-दराज के गांव जुड़ेंगे और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र रूप से आर्थिक विकास होगा। इससे स्वयं सहायता समूहों के लिए आजीविका के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होगा। एजीईवाई की प्रमुख बातों पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जून, 2016 में राज्य परिवहन मंत्रियों की हुई बैठक में विचार किया गया और राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने इस पहल की प्रशंसा की।

क्या है

1. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) को दिये जाने वाले समुदाय निवेश कोष (सीआईएफ) का उपयोग स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को समर्थन देने में किया जाएगा।

2. समुदाय निवेश कोष से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थी सदस्य को सीबीओ द्वारा वाहन खरीदने के लिए 6.50 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर वाहन का स्वामित्व सीबीओ के पास होगा और सीबीओ स्वयं सहायता समूह के सदस्य को वाहन पट्टे पर चलाने और पट्टे का किराया सीबीओ को देने के लिए कहेगा।
3. एजीईवाई प्रारंभ में पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक को परिवहन सेवा चलाने के लिए 6 वाहन दिये जायेंगे।
4. चालू वर्ष के दौरान 8 राज्यों आंध्रप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 52 ब्लॉकों इस योजना का लागू करने की स्वीकृति दी गई है और इसके लिए 16.06 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 10.16 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी और शेष राशि संबंधित राज्यों द्वारा दी जायेगी।
5. राज्य ब्लॉकों का चयन उन ब्लॉकों में से करेंगे जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है और जहां परिपक्व समुदाय आधारित संगठन पहले से काम कर रहे हैं। ब्लॉकों तथा मार्गों के चयन में पिछड़ापन, परिवहन संपर्क का अभाव और सतत सेवा की संभावना जैसी बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
6. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) द्वारा चुने गए ब्लॉकों में संभावना अध्ययन और यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा। मार्गों तथा सतत आधार पर चलाए जाने वाले वाहनों की संख्या और क्षमता की पहचान की जाएगी।
7. यह अध्ययन तकनीकी रूप से उन मजबूत संगठनों द्वारा किया जाएगा जो परिवहन नेटवर्क नियोजन में विशेषज्ञता रखते हैं। 6.50 लाख की लागत सीमा के अंदर वाहन या तो ई-रिक्शा होगा या श्री विहलर या फोर विहलर होगा।
8. एसआरएलएम द्वारा वाहनों के लिए परमिट जारी करने के काम में राज्य परिवहन के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। वाहन चलाने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि वैध परमिट, रोड़ टैक्स परमिट, वैध बीमा पालिसी जैसी सभी आवश्यक कानूनी और वैधानिक आवश्यकता पूरी की गई है।

सिंधु जल संधि पर PAK को झटका

सिंधु जल संधि पर भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर पनबिजली परियोजना बनाने की इजाजत है। दोनों देशों के बीच विवाद में विश्व बैंक मध्यस्थ की भूमिका में है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत वॉशिंगटन में सितंबर में होगी। पिछले साल पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा (330 मेगावाट) और रातले (850 मेगावाट) पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन पर सवाल उठाते हुए विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया था।

क्या है

1. भारत और पाकिस्तान के बीच यही विवाद है कि यह डिजाइन संधि के अनुकूल है या नहीं। किशनगंगा प्रोजेक्ट झेलम की सहायक नदी है, जबकि रातले प्रोजेक्ट चेनाब नदी से जुड़ा हुआ है।
2. संधि में दोनों नदियों को पश्चिमी नदी के तौर पर परिभाषित किया है। पाकिस्तान इन नदियों के पानी का असीमित इस्तेमाल कर सकता है।
3. विश्व बैंक ने मंगलवार को फैक्टशीट जारी कर कहा कि भारत जिन रूपों में नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सद्भावना और सहयोगपूर्ण माहौल में हुई।
4. भारत और पाकिस्तान के बीच 57 साल पहले यह संधि हुई थी। इस अंतरराष्ट्रीय जल संधि पर 19 सितंबर, 1960 को

एक नजर में सिंधु नदी :

1. 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु नदी का क्षेत्रफल
2. 47 फीसदी क्षेत्र पाकिस्तान में आता है
3. 39 फीसदी इलाका भारत, 8 प्रतिशत चीन और 6 प्रतिशत अफगानिस्तान में
4. 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाक राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।

5. इसके तहत सिंधु घाटी की 6 नदियों का जल बंटवारा हुआ था। इन नदियों को दो हिस्सों (पूर्वी और पश्चिमी) दो हिस्सों में बांटा गया था। पूर्वी पाकिस्तान की तीन नदियों (व्यास, रावी और सतलुज) का नियंत्रण भारत के पास है। जबकि सिंधु, चेनाब, झेलम का नियंत्रण पाक के पास है।

अमेरिकी जीपीएस पर निर्भर नहीं रहेगा भारत

भारत का रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र अब अमेरिका निर्मित जीपीएस पर निर्भर नहीं रहेगा। इस दिशा में 4 अगस्त 2017 को महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसरो की क्षेत्रीय स्थिति प्रणाली एनएवीआइसी अब भारतीय परमाणु घड़ी पर निर्भर रहेगी। इसरो के आइएसटीआरएसी सेल और राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

क्या है

1. इसके तहत अंतरिक्ष एजेंसी को राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला समय की सटीकता तय करने में मदद करेगी। समय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस कदम से अंतरिक्ष एजेंसी अब अमेरिकी जीपीएस पर निर्भर नहीं रहेगी।
2. विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के तहत एनपीएल संस्थान भारत के पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना आजादी से पहले ही हुई थी।
3. अपनी परमाणु घड़ियों से यह भारतीय मानक समय मुहैया कराता है। ये परमाणु घड़ियां अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो (बीआइपीएम) फ्रांस की परमाणु घड़ियों के साथ संबद्ध हैं।
4. बीआइपीएम ही दुनिया को वैश्विक समय समन्वय (यूटीसी) मुहैया कराता है। दुनिया में 400 परमाणु घड़ियां हैं और इनमें से भारत के पास चार से पांच घड़ियां हैं। ये घड़ियां एकदम सटीक होती हैं।
5. 10 करोड़ साल में इन घड़ियों के काम में एक सेकंड की चूक होती है। इस तरह के अत्यंत कीमती समय में नैनो सेकंड का भी अपना महत्व होता है। यह इसरो के उपग्रहों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8वीं तक फेल न करने की नीति खत्म करने का बिल पेश

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत बच्चों को स्कूल में 8वीं तक फेल न करने की नीति खत्म करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाह ने शुक्रवार को यह 'बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017' पेश किया। इस विधेयक को कैबिनेट ने तीन अगस्त को मंजूरी दी थी।

क्या है

1. विधेयक में किए गए प्रस्तावों के मुताबिक, राज्यों को यह अधिकार होगा कि अगर बच्चे वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाएं तो वे उन्हें 5वीं या 8वीं कक्षा में अथवा दोनों ही कक्षाओं में रोक लें। लेकिन, ऐसा करने से पहले उन्हें बच्चों को दूसरा मौका देना होगा।
2. राज्यों को यह अधिकार भी होगा कि वे चाहें तो वर्तमान स्थिति बनाए रखते हुए उन्हें 8वीं कक्षा तक फेल ही न करें।
3. दरअसल, पिछले कुछ सालों से कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फेल न करने की नीति की वजह से बच्चों के सीखने के स्तर पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाते रहे हैं।

कोर्ट निरस्त कर सकता है 35 ए

जम्मू कश्मीर के नागरिक होने का दर्जा तय करने का राज्य सरकार को हक देने वाला अनुच्छेद 35ए आजकल सवालों में है। सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत दो याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अनुच्छेद 35ए में बदलाव करने या इसे समाप्त करने का सरकार के पास क्या अधिकार है और प्रक्रिया क्या है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है। कानूनविदों की मानें तो सरकार के लिए इससे छेड़छाड़ करना बहुत आसान नहीं है लेकिन कोर्ट संवैधानिक मानदंडों की कसौटी पर खरा न पाने पर इसे निरस्त कर सकता है।

क्या है

1. संविधान के पीछे एपेन्डिक्स में शामिल अनुच्छेद 35ए सवालों में इसलिए है क्योंकि इसे संविधान में शामिल करने से पहले अन्य अनुच्छेदों की तरह संसद में चर्चा नहीं हुई और न ही ये संसद से पास होकर आया। ये अनुच्छेद 1954 में राष्ट्रपति आदेश से संविधान में शामिल हुआ। इसे संविधान का हिस्सा बनाने से पहले तय प्रक्रिया पूरी न होने के आधार पर एक वर्ग लगातार इसकी खिलाफत करता आ रहा है।
2. यह भी तर्क है कि जब राष्ट्रपति के आदेश से इसे शामिल किया जा सकता है तो फिर राष्ट्रपति उसे वापस भी ले सकते हैं। लेकिन पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि अब ये अनुच्छेद संविधान का हिस्सा है और कानूनन इसकी उतनी ही अहमियत है जितनी अन्य अनुच्छेदों की है। इसमें कोई भी बदलाव या संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनानी होगी, जो कि बहुत आसान नहीं है। हालांकि वे मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कसौटी पर कमजोर पाकर इसे निरस्त कर सकता है।
3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है जिसके मुताबिक संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए इसके बाद पचास फीसद राज्य विधानसभाओं से मंजूर होने के बाद ही संशोधन हो सकता है। लेकिन संविधानविद सुभाष कश्यप का मानना है कि अनुच्छेद 35ए में बदलाव के लिए संविधान संशोधन की तय प्रक्रिया पूरी करना जरूरी नहीं है इसे दूसरे तरीके से भी कानूनन और संवैधानिक तौर पर हटाया व बदला जा सकता है।
4. कश्यप कहते हैं कि अनुच्छेद 35ए के प्रेसीडेंशियल आदेश की शुरुआत में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से ये आदेश जारी कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया से इसे हटाया या बदला जा सकता है। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर सरकार से मशविरा करके अनुच्छेद 35ए के प्रेसीडेंशियल आदेश को वापस ले सकते हैं या इसमें बदलाव कर सकते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय

चीन परिवार नियोजन की नई नीति लागू

चीन में अभी तक परिवार नियोजन से बाहर रहे मुस्लिम समुदाय को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। नई परिवार नियोजन नीति अशांत शिनजियांग प्रांत में भी लागू कर दी गई है। इस प्रांत में उइगर मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। चीन ने चार दशक पुरानी एक बच्चे की नीति में पिछले साल ढील देते हुए लोगों को दो बच्चों को जन्म देने की इजाजत दे दी थी। एक बच्चे की यह नीति सिर्फ बहुसंख्यक हान समुदाय पर ही लागू थी। चीन की 138 करोड़ आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 90 फीसद से अधिक है। इस नीति के दायरे से मुस्लिमों और तिब्बतियों समेत सभी अल्पसंख्यक समुदायों को बाहर रखा गया था।

क्या है

1. शिनजियांग में 28 जुलाई से नई नीति लागू कर दी गई है। इसके दायरे में अब मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों को भी लाया गया है।
2. चीनी विश्लेषकों का कहना है कि समान परिवार नियोजन नीति सभी जातीय समूहों के लिए है। इस कदम से जातीय समानता को बढ़ावा मिलेगा।
3. शिनजियांग में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब परिवार नियोजन नीति से मिली छूट का फायदा नहीं उठा सकते हैं। 28 जुलाई से प्रांत के सभी शहरी जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। जबकि ग्रामीण जोड़े तीन बच्चों के माता-पिता बन सकते हैं।
4. वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार शिनजियांग की आबादी 2.39 करोड़ है। प्रांतीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 2010 की जनसंख्या के आधार पर बताया कि प्रांत में 87 लाख हान समुदाय के लोग हैं।
5. उनकी आबादी साल 2000 की तुलना में 16.77 फीसद बढ़ी। जबकि 1.3 करोड़ अल्पसंख्यक (ज्यादातर उइगर) हैं। इनकी इस अवधि में आबादी 19.12 फीसद बढ़ी।

आसियान में अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहा चीन

दक्षिण चीन सागर पर चीन आखिरकार आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की एसोसिएशन) में अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहा। दो दिन की गहमागहमी और बैठकों के दौर के बाद आसियान देशों ने बेहद हल्का साझा बयान जारी किया। इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे चीन नाराज न हो। आसियान में दस देश हैं। बयान जारी करने से पूर्व आसियान विदेश मंत्रियों ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर वार्ता के उस फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की जिसमें चीन के पक्ष वाले प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में वांग ने कहा कि यह हमारे संयुक्त प्रयासों का बेहद महत्वपूर्ण परिणाम है।

क्या है

1. इससे पहले सम्मेलन के पहले दिन भी दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर विचार हुआ। एक संयुक्त बयान भी जारी होना था, लेकिन उसके मसौदे पर सहमति नहीं बन पाई। विचार-विमर्श के बाद संयुक्त बयान जारी करने का कार्यक्रम बना, लेकिन सदस्य देशों में सहमति नहीं बन पाई थी।
2. रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र पर दावा करने वाले वियतनाम ने संयुक्त बयान में चीनी अतिक्रमण पर कठोर भाषा का इस्तेमाल करने की बात कही तो चीन के मजबूत सहयोगी कंबोडिया ने उस पर आपत्ति जता दी।
3. बैठक में शामिल एक राजनयिक ने बताया कि वियतनाम अपने रुख पर अड़ा हुआ था जबकि कंबोडिया चीन के हितों की पैरोकारी कर रहा था। जबकि, फिलीपींस फायदा उठाने वाले बिचौलिये के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा था।
4. उल्लेखनीय है कि आसियान के सदस्य देश वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रूनेई इस समय अपनी जल सीमा के अधिग्रहण का खतरा झेल रहे हैं।
5. चीन दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्से पर अपना अधिकार बताता है। इस दावे के साथ ही उसने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कृत्रिम द्वीप बनाकर वहां अपनी सेना तैनात कर दी है।
6. भारत ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य में आसियान का केंद्रीय स्थान है। इसमें दुनिया के व्यापक हितों को प्रदर्शित करने की विशिष्ट क्षमता है।
7. 15 वीं आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पिछले 50 सालों में आसियान ने क्षेत्र के उपनिवेशवाद के बाद की कई चर्चाओं को पीछे छोड़ दिया है।
8. भारत आसियान के साथ गठजोड़ की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।

पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि को नकारा

पाकिस्तान ने कहा कि वह हाल ही में प्रभावी परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं करता है। इस संधि में सभी पक्षों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 7 जुलाई को हुई यह संधि प्रक्रिया और लक्ष्य दोनों ही मामलों में शर्तें पूरी नहीं करती है।

क्या है

1. संयुक्त राष्ट्र में 120 से ज्यादा देशों ने मतदान के जरिये परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध के लिए पहली वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किया था।
2. इस मतदान में चीन और अमेरिका समेत आठ परमाणु हथियार संपन्न देशों ने हिस्सा नहीं लिया था।
3. पाकिस्तान का कहना है कि अन्य परमाणु हथियार संपन्न देशों की तरह पाकिस्तान भी इस संधि का हिस्सा नहीं बनेगा।
4. पाकिस्तान का कहना है कि जो संधियां सभी पक्षों के हित का ध्यान नहीं रख सकतीं, उनसे लक्ष्य हासिल नहीं होता। पाकिस्तान खुद को इस संधि के किसी प्रावधान से बंधा हुआ नहीं मानता।

भारत और रूस के बीच में 'वार गेम्स'

भारत और रूस क्षेत्र में सुरक्षा हालात की जरूरतों को देखते हुए अक्टूबर में वार गेम्स शुरू करने जा रहे हैं। इस युद्ध क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं, नौसेनाएं और वायु सेनाएं अपने रणकौशल दिखाएंगी। सूत्रों का कहना है कि

युद्ध अभ्यास इंद्र रूस में 19 अक्टूबर और 29 अक्टूबर तक होगा। रूस में पर्वतीय क्षेत्र व्लादिवोस्तोक समेत तीन स्थानों पर यह सैन्य अभ्यास होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बेहतर करना है।

क्या है

1. ऐसा पहली बार है जब दोनों देशों की तीनों सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। इसमें भारतीय सेना के कुल 350 सैन्य अफसर हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास के लिये सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व मेजर जनरल रैंक के अफसर करेंगे। नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों में भी पर्याप्त संख्या में अफसर होंगे।
2. गौरतलब है कि यह भारत और रूस के बीच यह सैन्य अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब चीन सीमा विवाद को लेकर भारत को आंखें दिखवा रहा है और पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिये और अन्य मुद्दों पर पूरा समर्थन दे रहा है।
3. रूस लंबे समय से भारत का रक्षा क्षेत्र में सहयोगी रहा है। इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान दोनों देशों ने आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने और संयुक्त रूप से हथियारों और हार्डवेयर पर काम करने के लिये समझौते किये थे।

भारत और स्वीडन के बीच आईपीआर पर समझौता

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्वीडन के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन में एक ऐसी व्यापक और सुगम व्यवस्था कायम करने का प्रावधान है जिसके जरिये दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये उत्कृष्ट पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान करेंगे।

क्या है

1. समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई जाएगी जो इन क्षेत्रों में निम्न सहयोग गतिविधियों के बारे में निर्णय करेगी।
2. दोनों देशों के लोगों, व्यापारियों और शैक्षिक संस्थानों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में उत्कृष्ट पद्धतियों, अनुभवों और जानकारियों का आदान-प्रदान।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और संपर्क गतिविधियाँ।

क्या होगा प्रभाव?

1. यह भारत को बौद्धिक संपदा प्रणालियों में अनुभव का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, जिससे दोनों देशों के उद्यमियों, निवेशकों और व्यापारियों को महत्वपूर्ण लाभ पहुँचेगा।
2. दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट पद्धतियों के आदान-प्रदान से भारत के विविध प्रकार के बौद्धिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और उनका बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।
3. यह समझौता वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनने की भारत की यात्रा में ऐतिहासिक सिद्ध होगा और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के लक्ष्यों को बढ़ावा देगा।

पृष्ठभूमि

1. आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में की गई थी।
2. थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर इसके संस्थापक सदस्य थे।
3. वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य हैं।
4. इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
5. इसका उद्देश्य सदस्य देश आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिये साझा प्रयास करते हैं।
6. यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।
7. इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता फिलिपींस के पास है।
8. इस समूह के गठन का यह 50वाँ वर्ष है।
9. यह भारत-आसियान संवाद साझेदारी का 25वाँ वर्ष है।

4. संयुक्त रूप से या किसी एक राष्ट्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और विकास संगठनों तथा लघु और मध्यम उद्यमों के बीच बौद्धिक संपदा के बारे में उत्कृष्ट पद्धतियों, अनुभवों और जानकारियों का आदान-प्रदान।
5. बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में आटोमेशन और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन, नव प्रलेखन और सूचना प्रणालियों और बौद्धिक संपदा के प्रबंधन की प्रक्रियाओं के विकास में सहयोग।
6. डिजिटल वातावरण, विशेषकर कॉपीराइट मुद्दों के संबंध में बौद्धिक संपदा कानून के उल्लंघन के बारे में जानकारियों और उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान-प्रदान।

आसियान की 50वीं वर्षगाँठ

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ क्षेत्रीय एकीकरण का एक अनोखा उदाहरण है। इस वर्ष यह संगठन अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ मना रहा है। अपनी स्थापना से अब तक इसने साझे आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा तय की है, जो अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक संगठनों के लिये अनुकरणीय है।

क्या है

1. आसियान का एकीकरण इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की परिपक्वता पर निर्भर करता है।
2. पिछले कुछ वर्षों में चीन और भारत का एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने से आसियान पर व्यापार के उदारीकरण को तत्काल प्रभावी करने की आवश्यकता महसूस हुई है।
3. वर्ष 2007 में आसियान ने माल, सेवाओं, पूंजी और कुशल कर्मियों की मुक्त आवा-जाही के लिये एक वैधानिक चार्टर अपनाया।
4. वर्ष 2015 में आसियान आर्थिक समुदाय के शुभारंभ के साथ, आसियान एक एकीकृत एकल बाज़ार के रूप में उभरने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने और एक एकीकृत आवाज के साथ शेष विश्व के साथ जुड़ने के लिये तैयार हो गया है।

अर्थशास्त्र

‘भारत 2022’ की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 अगस्त 2017 को एक नए ईटीएफ की घोषणा की है, जिसका नाम भारत-22 रखा गया है, इसमें करीब 22 कंपनियों, बैंकों और SUUTI होल्डिंग्स के शेयर होंगे। भारत-22 कुल 6 सेक्टर्स को कवर करेगा।

क्या है

1. इसमें चार बैंकिंग स्टॉक शामिल होंगे, जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक।
2. सीपीएसई के अलावा नाल्को, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल और कोल इंडिया जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें 9 अन्य सार्वजनिक उपक्रम और साथ ही इसमें साथ ही आरईसी और पीएफसी भी शामिल होंगे।
3. आईटीसी में सुट्टी की होल्डिंग को भी शामिल किया गया है। इसमें शामिल 90 फीसद इक्विटी में वायदा कारोबार किया जाता है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल इसका फंड मैनेजर है।
4. भारत-22 के पास सुट्टी की कुल होल्डिंग का 15.2 फीसद हिस्सा होगा। 22 स्टॉक्स में से, आईओसी, बीपीसीएल, नाल्को के पास भारत-22 में 4.4 फीसद का वेटेज होगा।
5. वहीं पावर ग्रिड के पास 7.9 फीसद, एक्सिस बैंक (7.7 फीसद), एसबीआई (8.6 फीसद) और कोल इंडिया (3.3 फीसद) के पास ईटीएफ में 3 से 8 फीसद का वेटेज होगा।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक

राज्यसभा ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है, जो प्रमुख बैंकों के ऋण डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को निर्देश देने में सक्षम बनाता है। लोकसभा द्वारा यह

विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका था। अब यह विधेयक, **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017** का स्थान लेगा।

क्या है

1. भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ एक नियामक संस्था भर नहीं है बल्कि यह सार्वजनिक ऋण प्रबंधन जैसे अन्य कार्य भी करता है।
2. भारत के कुछ बैंक बड़े डिफॉल्टर्स एवं गैर-निष्पादित संपत्तियों की समस्या से जूझ रहे हैं। अतः सरकार बैंकों को उनके प्रमुख डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऋण वसूली के लिये उचित कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करना चाहती है।
3. **ऋण वसूली के लिये पहले से मौजूद नियमों में समय अधिक लगता था। नई समानांतर व्यवस्था अब अधिक प्रभावी होगी।**

गंगा से 100 मीटर तक 'नो डेवलपमेंट जोन'

गंगा को निर्मल बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि बीते दो साल में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होने के बावजूद गंगा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एनजीटी ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गंगा नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी तक 'नो डेवलपमेंट जोन' भी घोषित किया है। इसका मतलब है यह है कि गंगा के किनारे इतने क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं हो सकेगी। एनजीटी ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे भेजे गए 32 साल पुराने मामले की सुनवाई के बाद दिया।

क्या है

1. एनजीटी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ कहा है कि गंगा नदी से 500 मीटर की दूरी तक अगर कोई कचरा डालेगा तो उस पर हर बार भारी भरकम 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
2. कानपुर के निकट जाजमऊ से गंगा में गिरने वाली खतरनाक क्रोमियम युक्त गंदगी को रोकने के लिए एनजीटी ने टेनरियों की एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह में कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है।
3. एनजीटी का कहना है कि अगर यह कार्ययोजना तैयार नहीं की जाती है तो टेनरियों को जाजमऊ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गंगा में प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रहे एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा को निर्मल बनाने की योजना पेश करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
4. एनजीटी के अध्यक्ष **न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने 543 पेज** के अपने आदेश में कहा कि गंगा देश की पवित्र नदियों में से एक है। ऐसे में अविरल प्रवाह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
5. ट्रिब्यूनल ने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 500 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए।
6. वहीं ऐसा करने वालों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए। इन्तहा ही नहीं, एनजीटी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी आदेश दिया है, कि वह यह सुनिश्चित करें, कि गंगा के किनारों, खासकर घाटों पर स्वच्छता को लेकर तय किए गए नियमों का

कौन कौन सी कंपनियां है शामिल

1. जिन कंपनियों को आठ अगस्त को स्टेज VI के जीएसएम फ्रेमवर्क में भेज दिया गया है उनमें एटीएल इंटरनेशनल, अल्का इंडिया, बिड़ला कोटसिन, बिड़ाल कैपिटल, ब्लू चिप इंडिया, एआरसीसी इंफ्रा, जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स, जय माता ग्लास, पिनकॉन स्पिरिट, आरईआई एग्रो, गैलेंट इस्पात, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, एसक्यूएस बीएफएसआई, रोहित फेरो और असम कंपनी का नाम शामिल है।
2. जीएसएम फ्रेमवर्क के प्रावधान के तहत इन सिक्टोरिटीज में ट्रेडिंग नहीं की जा सकेगी। इन कंपनियों में महीने के पहले सोमवार को ही ट्रेडिंग हो पाएगी।
3. एक अधिकारी का कहना है कि करीब 26 चाटर्ड एकाउंटेंट (सीए) की आईसीआई ने पहचान की है जिन्होंने अवैध रूप से शेल कंपनियों की मदद की थी।

कड़ाई से पालन हो।

331 शेल कंपनियों की पहचान

बाजार नियामक सेबी ने शेल कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए सोमवार को 331 कंपनियों की सूची जारी कर दी है। इनमें लिस्टेड कंपनियां भी हैं। काले धन पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से सेबी ने कहा है कि इन कंपनियों में इस महीने ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। इनमें ट्रेड बंद कर दिया गया है।

क्या होती है शेल कंपनियां

1. शेल कंपनी वे संदिग्ध कंपनियां होती हैं जो आमतौर पर लॉन्ड्रिंग के लिए अवैध फंड का इस्तेमाल करती हैं।
2. इन कंपनियों के संचालन की बात की जाए तो इनमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता, इनमें केवल कागजों पर एंटीज दर्ज की जाती हैं। हालांकि, कंपनीज एक्ट में शेल कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
3. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार, इन सूचीबद्ध सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग को ग्रेडेड सर्वेलन्स मेशर (जीएसएम) के स्टेज VI में तुरंत प्रभाव से रखना चाहिए। अगर कोई सूचीबद्ध कंपनी पहले से जीएसएम के किसी भी स्टेज के तहत पहचान कर ली गई है तो उसे जीएसएम के स्टेज VI में सीधे तौर पर भेजना होगा।
4. जीएसएम प्रेमवर्क के स्टेज VI के तहत इन कंपनियों में महीने में केवल एक बार ट्रेडिंग होगी। निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए 200 फीसद मार्जिन रखना होगा।
5. इन सिक्योरिटीज में किसी भी तरह की तेजी पिछले बंद भाव के स्तर से ऊपर नहीं होंगी। साथ ही एक्सचेंज इन कंपनियों के फंडामेंटल्स की जांच करेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड-2

राजकोषीय घटनाक्रम

1. वर्ष 2016-17 में केन्द्र सरकार के राजकोषीय परिणाम कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि, पूंजीगत खर्चों में निरंतरता और गैर-वेतन/पेंशन राजस्व व्यय के समेकन के रूप में चिन्हित हुए। इसके परिणामस्वरूप सरकार को वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 3.5 प्रतिशत तक सीमित रखने में मदद मिली।
2. वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में क्रमिक राजकोषीय समेकन मार्ग को अपनाया गया है। वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे के कम होकर जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर आ जाने की आशा है। एफआरबीएम रूपरेखा के तहत राजकोषीय घाटे के जीडीपी का तीन प्रतिशत रहने का जो लक्ष्य तय किया गया है उसके वर्ष 2018-19 में प्राप्त होने की आशा है।
3. 2017-18 के बजट में अनेक प्रक्रियागत सुधारों की शुरुआत की गई। इनमें रेलवे बजट को केन्द्रीय बजट में शामिल करना, केन्द्रीय बजट को निर्धारित तिथि से लगभग एक माह पहले यानी 1 फरवरी को पेश करना, खर्च को 'योजना' और 'गैर-योजना' व्यय में वर्गीकृत करने की परम्परा को समाप्त करना और अगले दो वित्त वर्षों के लिए प्रत्येक मांग हेतु अनुमानित व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) के साथ मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा वक्तव्य की पुनर्संरचना इन सुधारों में शामिल हैं।
4. आगे चलकर जीएसटी इन महत्वपूर्ण राजकोषीय नीतिगत पहलों से भी अधिक चर्चा में रहा, जिसे 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया और उसमें केन्द्र एवं राज्य स्तरीय अनेक करों का समावेश कर दिया गया है। इससे भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान नीतिगत दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती की। हालांकि, रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के तहत फरवरी, 2017 से समायोजन के बजाय तटस्थ रुख पर फोकस करने लगा। अगस्त, 2017 में रेपो रेट 6.00 प्रतिशत और रिजर्व रेपो रेट 5.75 प्रतिशत रहा।

2. 9 नवंबर, 2016 को पुराने बड़े नोटों का चलन बंद करने के निर्णय से बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा प्रचलन काफी हद तक घट गया। 31 मार्च, 2017 तक मुद्रा प्रचलन में 19.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि आरक्षित मुद्रा में 12.9 प्रतिशत की कमी आंकी गई।
3. बैंकों से कर्जों का उठाव बाद में और भी घटता चला गया। वर्ष 2016-17 के दौरान सकल बकाया बैंक ऋण में औसतन लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान उद्योग जगत को मिले औसत सकल बैंक ऋण में 0.2 प्रतिशत की कमी आंकी गई।
4. अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में विकास की सुस्त गति और बढ़ती ऋणग्रस्तता का असर बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर पड़ा, जो चिंता का विषय है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात सितम्बर, 2016 के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 में 9.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।
5. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेश निरंतर तेज गति हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शून्य बैलेंस वाले खातों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, जो मार्च 2015 के लगभग 58 प्रतिशत से कम होकर दिसम्बर, 2016 में तकरीबन 24 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

कीमतें और महंगाई

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। सीपीआई पर आधारित महंगाई दर जून, 2017 में अत्यंत कम होकर 1.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।
2. वर्ष 2016-17 के दौरान समस्त जिंस समूहों में व्यापक कमी आंकी गई। सर्वाधिक कमी खाद्य पदार्थों की कीमतों में दर्ज की गई।
3. विगत महीनों में महंगाई दर बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहने वाली खाद्य महंगाई में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय कमी आई है। मानसून के सामान्य रहने के साथ-साथ दालों और सब्जियों की आपूर्ति बेहतर होने से ही खाद्य महंगाई में कमी संभव हो पाई है। विगत कुछ महीनों के दौरान मुख्य महंगाई दर में भी कमी दर्ज की गई है, जो अंतर्निहित रुख को दर्शाती है।
4. विगत कुछ महीनों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई में सामंजस्य देखने को मिली है।
5. वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में ही महंगाई कम हुई है। हाल के महीनों में ग्रामीण और शहरी महंगाई के बीच अंतर घट गया है।

जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और ऊर्जा

1. भारत ने 2 अक्टूबर, 2016 को पेरिस समझौते का अनुमोदन किया। वर्ष 2020 के बाद की अवधि के लिए भारत के कदम उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) पर आधारित हैं।
2. भारत के एनडीसी में वर्ष 2005 के स्तर के मुकाबले वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33-35 प्रतिशत की कमी करने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर स्थापित विद्युत क्षमता (संचयी) का 40 प्रतिशत करने और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष कवर के जरिये 2.5-3 गीगाटन उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन भंडार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
3. भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्वयं ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत दुनिया में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक पांच गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट बायोमास और 5 गीगावाट की अल्प पनबिजली क्षमता शामिल हैं।
4. भारत के वित्तीय क्षेत्र में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत जेनरेटर्स, बायोमास आधारित विद्युत

जेनेरेटरो, पवन चक्कियों, सूक्ष्म पनबिजली संयंत्रों इत्यादि के लिए 15 करोड़ तक के बैंक ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र वाले कर्जों का हिस्सा माना जाएगा। विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) से जुड़े मानकों को और भी उदार बना दिया गया है, ताकि हरित परियोजनाएं सीमा पार ऋण जुटाने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मई 2017 में हरित बांड जारी करने की रूपरेखा पेश कर दी है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

1. भारत में खेतों का औसत आकार छोटा है और 1970-71 से उसमें कमी आती जा रही है। छोटी काश्तकारी कृषि में अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ उठाने में प्रमुख बाधा है।
2. कृषि की प्रगति का आकलन विभिन्न फसलों के वैश्विक उत्पादन के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि किसानों की आय में इज़ाफा हो सके।
3. **कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऋण एक महत्वपूर्ण जरिया है।** किसानों के लिए ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का दबदबा चिंता का प्रमुख विषय है। कृषि ऋण के आवंटन में क्षेत्रीय असमानता को भी दूर किया जाना आवश्यक है।
4. भारत में बागवानी के सामने जो प्रमुख चुनौतियां मौजूद हैं, उनमें पैदावार के बाद होने वाला नुकसान, बेहतर बीजों की उपलब्धता और छोटे किसानों के लिए अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंच में कमी शामिल हैं।

उद्योग एवं संरचना

1. 2015-16 के दौरान औद्योगिक कामकाज 8.8 प्रतिशत था, जिसमें 2016-17 में कमी हुई और वह 5.6 प्रतिशत हो गया।
2. 2011-12 की नई श्रृंखला के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का औद्योगिक विकास बताता है कि 2016-17 में कुल विकास 5 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल यह 3.4 प्रतिशत था।
3. 8 प्रमुख उद्योगों आधारित सूचकांक के अनुसार 2016-17 में विकास 4.8 प्रतिशत रहा, जबकि 2015-16 में यह 3.0 प्रतिशत था।
4. भारतीय बाजारों में **इस्पात की डंपिंग को रोकने के लिए 2016 में सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य लागू किया था।** सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम सामने आ रहा है क्योंकि भारत द्वारा इस्पात के आयात में 36.2 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि 2016-17 में निर्यात 102 प्रतिशत तक बढ़ गया है।
5. कपड़ा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए। 22 जून, 2016 को सरकार ने कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र के लिए 6000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी। नवंबर, 2016 में धनराशि के जारी होने के बाद कपड़ा निर्यात में तेजी देखी गई।
6. **भारतीय घरेलू हवाई सेवाओं का भारत केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय यातायात में बहुत कम हिस्सा रहा।**
7. विदेशी हवाई सेवाओं द्वारा 6वीं मुक्त सेवा का इस्तेमाल, भारत की अपनी क्षमता का कम उपयोग, 0/20 नियम और बेड़ों की कमी इसके लिए जिम्मेदार हैं।
8. **20 नवम्बर, 2015 को सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए उदय योजना शुरू की थी।** उदय योजना में शामिल होने वाले 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का कुल बकाया ऋण 3.82 लाख करोड़ रुपये था। अब तक 15 राज्यों ने कुल 2.09 लाख करोड़ रुपये के उदय बान्ड जारी किए हैं। इनके अलावा डिस्कॉम ने 0.23 लाख करोड़ रुपये कीमत के बांड जारी किए हैं।
9. उदय के शुरू होने के बाद सभी राज्यों का राष्ट्रीय औसत घाटा वित्त वर्ष 2016 में 21.1 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 20.2 प्रतिशत हो गया है। 2015-16 में बिलिंग क्षमता 81वां प्रतिशत थी, जो 2016-17 में 83 प्रतिशत हो गई। इस तरह इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अखिल भारतीय स्तर पर और 15 राज्यों ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए शुल्कों की समीक्षा जारी कर दी है।

10. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अप्रैल, 2017 तक 941 करोड़ रुपये की 57 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। 2018 के दौरान 15305 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 462 परियोजनाओं को पूरा कर लिये जाने की संभावना है। इनमें कुछ परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ अपने समय से चल रही हैं।

सेवा क्षेत्र

1. सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। 2016-17 में कुल मूल्य संवर्धन विकास में उसका हिस्सा 62 प्रतिशत है। बहरहाल, इस क्षेत्र की वृद्धि पिछले वर्ष की 9.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2016-17 में 7.7 प्रतिशत रही। इसके बावजूद यह 2 अन्य क्षेत्रों से अधिक और 15 प्रमुख क्षेत्रों में लगभग सबसे ऊपर कायम है।
2. सेवा क्षेत्र के विकास में नरमी आने का कारण 2 सेवा वर्गों के विकास की धीमी गति है। यह वर्ग कारोबार, होटल, यातायात, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं (7.8 प्रतिशत) तथा वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं (5.7 प्रतिशत) संबंधी है। कुल पूंजी निर्माण में सेवा क्षेत्र का हिस्सा मौजूदा मूल्य के आधार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2011-12 में यह 53.3 प्रतिशत था, जो 2015-16 में बढ़कर 60.3 प्रतिशत हो गया।
3. आमतौर पर 2014-15 और 2015-16 (27.3 प्रतिशत और 29.3 प्रतिशत) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय विकास हुआ है। यह विकास खासतौर से सेवा क्षेत्र (67.3 प्रतिशत और 15 सेवाओं में सर्वोच्च 64.3 प्रतिशत) में दर्ज किया गया है। बहरहाल, 2016-17 में कुल एफडीआई इक्विटी के प्रवाह में नरमी देखी गई और सेवा क्षेत्र (सर्वोच्च 15 सेवाएं) में एफडीआई इक्विटी के प्रवाह में भी गिरावट आई।

सामाजिक संरचना, रोजगार और मानव विकास

1. प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में बेहतर शिक्षण और माध्यमिक शिक्षा में लक्षित नामांकन स्तर में वांछित उपलब्धि मुख्य चुनौती है।
2. भारत में रोजगार की स्थिति एक बड़ी चुनौती है, जो अनौपचारिक, असंगठित और अनियमित कामगारों से संबंधित है। इसके संबंध में कम लोगों को रोजगार प्राप्त है, कुशलता की कमी है और श्रम बाजारों पर कठोर श्रम नियम हावी हैं। इसके अलावा अनुबंधित श्रम भी एक चुनौती है।
3. भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने में भी कई चुनौतियां हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक भूमिका कम हो रही है, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है और कई लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दर पर नहीं मिल पा रही हैं।
4. सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने शुरूआत से ही उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खुले में शौच जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है। अनुमान है कि यह संख्या 35 करोड़ से कम हो जाएगी।

क्या होता है जब कंपनी दिवालिया होती है

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच ने आईडीबीआई बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया कंपनियों की श्रेणी में डाल दिया है। दिवालिया कानून के मुताबिक, किसी कंपनी को इस श्रेणी में डालते ही बोर्ड के डायरेक्टर्स सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो क्या होता है।

क्या है

1. अगर कोई कंपनी रियल एस्टेट/ प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ी है और उसके दिवालिया होने की नौबत आती है, तो उस सूरत में निवेशक क्रेडिटर बन जाते हैं, क्रेडिटर भी दो तरह के होते हैं एक सिक्वोर्ड और दूसरे अनसिक्वोर्ड।
2. कंपनी के दिवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास जाता है और इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, जिसे यह जिम्मा सौंपा जाता है कि वो 180 दिनों के भीतर कंपनी को रिवाइव करने का प्रयास करे।

3. अगर कंपनी 180 दिनों के भीतर कंपनी रिवाइव हो जाती है तो कंपनी फिर से सामान्य कामकाज करने लग जाती है, नहीं तो इसे दिवालिया मानकर आगे की कार्यवाही की जाती है।
4. दिवालिया होने के बाद कंपनी Wind-up Petition दाखिल करती है। इसके बाद कंपनी अपनी कुल एसेट्स की बिक्री कर क्रेडिटर को पैसा चुका देती है, हालांकि इस सूरत में अक्सर निवेशकों को नुकसान ही होता है।
5. मान लीजिए अगर किसी कंपनी में दो लोगों ने 100-100 रुपए का निवेश कर रखा है और दिवालिया होने के बाद कंपनी की कुल वैल्यु 20 रुपए रह गई है तो इन दोनों निवेशकों को 10-10 रुपए की राशि बराबर-बराबर बांट दी जाएगी। ऐसे में इन दोनों को 90 रुपए का नुकसान होगा।
6. ऐसी स्थिति में निवेशकों के पास आखिरी रास्ता यह होता है कि निवेशक कोर्ट डॉक्टराइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल यानी यह साबित कर दें कि शुरुआत से ही कंपनी की मंशा निवेशकों का पैसा लेकर भागने की थी, तो ही आप कंपनी के प्रमोटर्स को लायबल (जवाबदेह) बना सकते हैं और इस सूरत में उनको आपका पैसा लौटाना होगा। फ्रीडम मोबाइल वाले मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था।

सॉफ्टबैंक विजन फंड ने किया बड़ा निवेश

दुनिया के सबसे बड़ी तकनीक आधारित फंड सॉफ्टबैंक विजन फंड ने फ्लिपकार्ट में निवेश किया है। इसके बाद सॉफ्टबैंक कंपनी में सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है। बिना निवेश राशि के खुलासा किए कंपनी ने कहा, “यह किसी भारतीय तकनीक कंपनी में अबतक का सबसे बड़ा निजी निवेश है।”

क्या है

1. यह निवेश कंपनी की ओर से घोषित की गई उस फाइनेंसिंग राउंड का हिस्सा है जहां फ्लिपकार्ट ने टेंसेंट, ईबे और माइक्रोसॉफ्ट से फंड जुटाया था। इस फाइनेंस राउंड के बाद फ्लिपकार्ट के पास बैलेंस शीट में 400 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त राशि होगी।
2. जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने पहली तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 50.1 फीसद की वृद्धि दर्ज की है। यह इजाफा कंपनी में विजन फंड को शामिल किए जाने के बाद दिखा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा निजी इक्विटी फंड माना जाता है। एक नए रिपोर्टेबल सेगमेंट के रूप में इसने एक मूल्यांकन लाभ (वैल्युएशन गेन) हासिल किया है।
3. इंटरनेट और दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने जून तिमाही के दौरान मुनाफे में 479.2 अरब युआन (4.33 अरब डॉलर) की वृद्धि दर्ज की है।
4. सॉफ्टबैंक ने मार्च के अंत में मौजूदा कारोबारी साल के लिए एक पूर्वानुमान जारी नहीं किया है क्योंकि उसका मानना है कि इसमें काफी सारे अनिश्चितता वाले कारक शामिल हैं। आपको बता दें कि सॉफ्टबैंक टेक्नोलॉजी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर काम करता है।

उच्च शिक्षा के लिए बनेगा विशेष स्थायी कोष

सरकार माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए फंड की कमी को दूर करने के लिए एक नया कोष बनाने जा रही है। इस कोष की राशि की समय सीमा वित्त वर्ष के साथ समाप्त नहीं होगी और जरूरत के मुताबिक कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस आशय के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस कोष के लिए राशि आयकर पर लगने वाले एजुकेशन सेस से ली जाएगी। मंत्रालय शुरुआती तौर पर 3000 करोड़ रुपये का कोष तैयार करना चाहता है। इस कोष का इस्तेमाल स्कूलों और स्नातक स्तर के कालेजों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा।

क्या है

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, यह फंड नॉन लैप्सेबल होगा। यानी वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद इसमें बची राशि को देश की समेकित निधि में वापस नहीं भेजा जाएगा। बल्कि सतत इस्तेमाल के लिए राशि उपलब्ध रहेगी। अभी तक मंत्रालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत

उच्च शिक्षा के विकास के लिए एजुकेशन सेस से मिलने वाली राशि को बचाए रखा जा सके। इसीलिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस संवाद की शुरुआत

गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) एसपीवी और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन मौजूद थीं। सहमति ज्ञापन पर जीईएम एसपीवी की ओर से जीईएम की सीईओ श्रीमती एस.राधा चौहान और सीआईआई की ओर से सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने हस्ताक्षर किए।

क्या है

इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय उद्योग और उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ सहभागी और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण कायम करने के लिए जीईएम संवाद स्थापित करना है। इस पहल के तहत जीईएम और भारतीय उद्योग मिलकर काम कर सकेंगे। इस पहल के तहत जीईएम और भारतीय उद्योग इस तरह मिलकर काम करेंगे :

1. जीईएम से जुड़ी जागरूकता पैदा करने और देशभर से उद्योग से जुड़े सदस्यों को शामिल करने।
2. भारतीय उद्योग के साथ सहयोग के लिए एक जीईएम उद्योग मंच बनाने जिससे उत्पादों के तकनीकी ब्यौरे और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के एसएलए के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार खासतौर से जिन्हें एमएसएमई से प्राप्त किया गया है, सभी साझेदारों का वार्षिक लोक उपाजर्न सम्मेलन आयोजित करने और सीआईआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में जीईएम संसाधन केंद्रों की स्थापना करने के लिए।
3. वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस जबरदस्त पहल के लिए जीईएम और सीआईआई को बधाई दी। उद्योगों की अन्य एसोसिएशनों के साथ भविष्य में इस तरह के कुछ और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

विज्ञान एवं तकनीकी

डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क

डेटा संरक्षण के विशेष महत्व को ध्यान में रखने के साथ-साथ देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

क्या है

1. इस समिति में सरकार, शिक्षाविद एवं उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं।
2. इस समिति को डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों की पहचान एवं अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
3. इसके साथ ही समिति डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के बारे में भी सुझाव देगी।
4. डेटा के संरक्षण से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।

जलीय वातावरण वाला ग्रह

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार सौरमंडल के बाहर किसी ग्रह के वातावरण में जलीय अणुओं की खोज की है। बृहस्पति के आकार वाला यह ग्रह धरती से 900 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका तापमान 2,500 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान पर लोहा ठोस की बजाय गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है।

क्या है

1. वैज्ञानिकों का कहना है कि पहली बार सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह पर समताप मंडल के प्रमाण मिले हैं।
2. समताप मंडल वातावरण की वह परत होती है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की हबबल दूरबीन की मदद से इस ग्रह के वातावरण से जुड़े प्रमाण जुटाए।

3. इस गैसीय ग्रह का नाम डब्ल्यूएसपी-121बी है। इसे हॉट ज्यूपिटर (गर्म बृहस्पति) भी कहा जा रहा है।
4. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के प्रोफेसर डेक डेमिंग ने कहा, इस ग्रह का समताप मंडल इतना ज्यादा गर्म है कि इसमें व्याप्त जल वाष्प के अणु चमकने लगते हैं।
5. इसी आधार पर हमने अध्ययन को अंजाम दिया है। यह ग्रह अपने तारे से न्यूनतम संभावित दूरी है और 1.3 दिन में उसका चक्कर पूरा कर लेता है।

जी.आई.एस. पोर्टल मैपिंग

केंद्र सरकार द्वारा लैंड एस्सिस्टिंग इंडस्ट्री (land assisting industry) की तकरीबन आधा मिलियन से अधिक भूमि का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया गया है। जी.आई.एस. (Geographic Information System) सक्षम डेटाबेस में 3000 के करीब औद्योगिक पार्कों/समूहों, कृषि/बागवानी फसलों की क्षेत्रवार उपलब्धता तथा खनिज उत्पादन आधारित सूचनाओं का विवरण शामिल किया गया है।

क्या है

1. जी.आई.एस. पोर्टल के अंतर्गत जल्द ही गोदामों, बिजली-ग्रिड एवं वित्तीय संस्थानों से संबद्ध जानकारीयों को शामिल किया जाएगा।
2. इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत भिन्न-भिन्न परियोजनाओं हेतु उद्यमियों द्वारा जमा किये गए आवेदनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (industrial infrastructure) संबंधी मांग को भी पूरा किया जाएगा।
3. इसका उद्देश्य वर्तमान में देश के औद्योगिक नीति-निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली सूचना विषमता (information asymmetry) को समाप्त करना है।
4. वर्तमान में इसके अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएँ संबद्ध है, जिनमें औद्योगिक पार्कों/समूहों; उद्योगों हेतु सामान्य सुविधाएँ; उद्योगों से संबद्ध भूमि एवं उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि; अनुमोदित एवं लंबित परियोजनाओं; राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन एवं विद्युत् संबंधी आधारभूत सुविधाओं; केंद्रीय/राज्य सरकारी प्रोत्साहन एवं निवेश/रोजगार आधारित लक्ष्यों इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है।

डेटाबेस में निहित सूचनाएँ

1. इस डेटाबेस के अंतर्गत प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/समूह से हवाईअड्डे/बंदरगाह की दूरी के संबंध में न केवल समस्त जानकारी बल्कि उस क्षेत्र विशेष का उपग्रह आधारित मानचित्र भी उपलब्ध है।
2. इसके अतिरिक्त कृषिगत फसलों उदाहरण के तौर पर - फाइबर फसलें, अनाज, तिलहन, वृक्षारोपण फसलें, दलहन एवं मसालों सहित बागवानी फसलों के संबंध में भी डेटा उपलब्ध है।
3. इस डेटाबेस को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion - DIPP) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (National e- Governance Division) के साथ-साथ बी.आई.एस.ए.जी (गुजरात सरकार के तहत अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान) द्वारा विकसित किया गया है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में अनुमान से पहले आए थे मानव

दक्षिण-पूर्व एशिया में मानव की मौजूदगी को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की मानें तो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया में इंसानों का आगमन मौजूदा 60-65 हजार साल के अनुमान से पहले हुआ था। मैक्वायर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी सुमात्रा (इंडोनेशिया) के लिडा अजर में स्थित एक गुफा से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह दावा किया है।

क्या है

1. शोधकर्ताओं ने गुफा से मिले साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर मानव के इस क्षेत्र में 73 हजार साल पहले आने की बात कही है।
2. पुरातत्व विशेषज्ञों ने जीवाश्म के अलावा चट्टान का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अलावा आधुनिक मानव (होमोसेपियंस) द्वारा भूमध्यरेखीय वन के इस्तेमाल के बारे में भी पहली बार प्रामाणिक साक्ष्य मिले हैं।
3. क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के गिल्बर्ट प्राइस ने बताया कि सवाना क्षेत्र (शुष्क) के निवासियों के लिए भूमध्यरेखीय क्षेत्र में रहना आसान नहीं होता है।
4. इसके बावजूद आधुनिक मानव ने बुद्धिमत्ता, योजना और तकनीक के प्रति गजब का अनुकूलन दिखाते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया के मौसम के अनुकूल खुद को ढाला।

ऑक्सीजन बिना कैसे जिंदा रहती है गोल्डफिश

वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है कि गोल्डफिश बिना ऑक्सीजन के कैसे लंबे समय तक जिंदा रहती है। इसी खासियत के चलते लोग इस मछली को एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। देखने में यह सुनहरी मछली बेहद आकर्षक लगती है।

क्या है

1. शोधकर्ताओं के अनुसार, इंसान और ज्यादातर जानवर बिना ऑक्सीजन के चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। जबकि गोल्डफिश और कृसियन कार्प जैसी मछलियां जमी झील की तलहटी में बिना ऑक्सीजन वाले पानी में कई दिन ही नहीं बल्कि महीनों तक जीवित रह सकती हैं।
2. दरअसल, इस दौरान यह मछली लेक्टिक एसिड को एथनॉल में तब्दील करने में सक्षम होती है और अपने गलफड़ों से इसे आसपास के पानी में फैला देती है। इससे वह अपने शरीर में खतरनाक लेक्टिक एसिड की बढ़ोतरी से खुद को बचा लेती है।
3. नार्वे की ओस्लो यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि इस अप्रत्याशित क्षमता के पीछे एक खास तरह का अणु संबंधी तंत्र काम करता है। रीढ़ वाले पशुओं में इस तरह की क्षमता अद्वितीय है।
4. उन्होंने पाया कि गोल्डफिश और कृसियन कार्प की मांसपेशियों में एक नहीं बल्कि प्रोटीन के दो सेट पाए जाते हैं। प्रोटीन का एक सेट दूसरी प्रजातियों के समान ही होता है जबकि दूसरा सेट ऑक्सीजन की गैरमौजूदगी में मजबूती से सक्रिय हो जाता है।

3डी चिप से बीमारियों का पता

भविष्य में बीमारियों का आसानी और कम खर्च में पता लगा पाना संभव हो सकेगा। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 3डी प्रिंटेड चिप बनाने में सफलता हासिल की है। यह ब्लड से बायोमार्कर या नमूना इकट्ठा कर बीमारी का बहुत ही कम समय में पता लगाने में सक्षम है।

क्या है

1. नए चिप माइक्रोफ्लूइडिक उपकरण (शरीर में मौजूद तरल पदार्थ से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मददगार) की तर्ज पर काम करता है।
2. आकार में यह चिप बहुत छोटा है। इसकी मदद से बायोमार्कर, सेल्स और अन्य सूक्ष्म शारीरिक संरचनाओं से जानकारी जुटाई जा सकेगी। इसके जरिये नमूनों को इकट्ठा कर संबंधित बीमारी का पता लगाया जा सकेगा।
3. ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी के ग्रेग नॉर्डिन ने बताया कि मौजूदा 3डी-प्रिंटेड उपकरण का आकार बड़ा है, जिसके कारण तरल पदार्थ से नमूना लेना संभव नहीं है। लेकिन, नया उपकरण सूक्ष्मतम नमूने लेने में सक्षम है। इससे बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
4. शोधकर्ताओं के मुताबिक इस चिप का आकार 18 बाय 20 माइक्रोमीटर है जो मौजूदा 100 माइक्रोमीटर से काफी छोटा है। चिप के निर्माण में रेजिन का इस्तेमाल किया गया है।

5. भारत जैसे विकासशील देशों में बीमारी का समय पर पता नहीं चल पाता है। ऐसे में अधिकांश मामलों में पीड़ितों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। नया चिप ऐसे देशों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

विविध

दूसरे सबसे अमीर आदमी

देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अंबानी ने पूंजी के मामले में चीन के कारोबारी ली का शिंग को पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलिनियर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस वर्ष 12.1 बिलियन डॉलर अपनी पूंजी में जोड़ लिए हैं। यह तब हुआ जब कंपनी के शेयर्स ने रिकॉर्ड हाई स्तर छुआ है। अब उनकी कुल पूंजी 34.8 बिलियन डॉलर हो गई है।

क्या है

1. वहीं, दूसरी ओर चीन के कारोबारी ली का शिंग की नेट वर्थ 33.3 बिलियन डॉलर हो गई है। बीते एक वर्ष में उनकी नेटवर्थ में महज 4.85 बिलियन डॉलर की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है।
2. वहीं बीते महीने पहले रिलायंस की ओर से 1500 रुपये का फोन लांच करने के एलान से जियो का मार्केट बेस बढ़ेगा।
3. रिपोर्ट के मुताबिक जियो की वजह से कंपनी का डेट (कर्ज) भी 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मुकेश अंबानी जियो में अबतक 31 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुके हैं।
4. कंपनी की 90 फीसद कमाई पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग से हो रही है। इसके अलावा रिटेल, मीडिया और नेचुरल गैस की माइनिंग में भी कमाई हो रही है।
5. 21 जुलाई को हुई रिलायंस की सालाना आम बैठक में अंबानी ने जियो को अपने एसेट का एक ज्वेल बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जियो देश का सबसे बड़ा डेटा सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट और एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म बनेगा।
6. रिलायंस जियो ने लांच होने के महज नौ महीनों में 117.3 मिलियन यूजर्स जोड़ लिए थे। इसके बाद यह कंपनी देश की चौथी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी बन गई है। यह सरकारी डेटा ब्लूमबर्ग ने जुटाया है। कंपनी की ओर से लॉन्च होने वाला 4जी जियो फोन वॉयस कमांड पर काम करेगा। यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा।

भारत के लिए प्रमुख खतरे

एक ताजा शोध सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के लोग आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख खतरा मानते हैं। चीन को देश के लिए तीसरा बड़ा खतरा माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सर्वेक्षण में शामिल 66 प्रतिशत लोगों ने इस्लामिक स्टेट को शीर्ष खतरा माना।

क्या है

1. 47 प्रतिशत ने कहा कि वे वैश्विक जलवायु परिवर्तन को प्रमुख खतरा मानते हैं।
2. इसमें कहा गया कि आईएसआईएस कुल 18 देशों में शीर्ष खतरे में शामिल रहा। इस देशों में ज्यादातर यूरोप, पश्चिमी एशिया के और अमेरिका हैं।
3. रिपोर्ट के अनुसार, 44 प्रतिशत ने कहा कि चीन भारत के लिए खतरा पैदा करता है। खतरों की सूची में इसके बिल्कुल करीब साइबर हमला (43 प्रतिशत) रहा।
4. गौरतलब है कि चीन और भारत के जवान सिक्किम सेक्टर के डोकलाम क्षेत्र में टकराव की स्थिति में हैं। इस क्षेत्र पर भारत का सहयोगी देश भूटान दावा करता है।

इंडो-नेपाल बार्डर पर बनेगा रेड कार्डर जोन

नेपाल में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और पाकिस्तान की लगातार घुसपैठ को देखते हुए सिक्किम की नया प्लान बनाया जा रहा है। इंडो नेपाल बार्डर की खुली सीमा पर रेड कार्डर जोन बनाने का फैसला किया गया है। 4 अगस्त 2017 को

कमिश्नर देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंटेलीजेंस की ओर से लगातार नेपाल में चीन की बढ़ती गतिविधियों की रिपोर्ट मिल रही है।

क्या है

1. इसे मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर खुली सीमा और नो मेंस लैंड के संवेदनशील क्षेत्रों में रेड कार्डर जोन बनाने का प्लान अंतिम रूप में है।
2. रेड कार्डर जोन का मास्टर ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए एसएसबी के साथ खुफिया एजेंसियों को लगाया गया है।
3. नेपाल के रास्ते नकली नोटों की तस्करी रोकने, आतंकी संगठनों के शातियों की घुसपैठ रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
4. उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश शासन से धनराशि प्रदान किये जाने के लिए प्रस्ताव बना लिया गया है।
5. इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों की सड़कों को दुरूस्त करने और नई सड़कों का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है।

टैंक को ध्वस्त करने वाली का खुला प्लांट

कई साल से भारतीय सेना को ऐंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल्स (एटीजीएम) की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। लड़ाई के दौरान इसके जरिए टैंकों को ध्वस्त किया जाता है। अब सेना को इस सिलसिले में बड़ी राहत मिल सकती है। भारत में एटीजीएम तैयार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का पहला प्लांट खुला है। यह कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड और इजरायल की राफेल अडवांसड डिफेंस सिस्टम्स का जॉइंट वेंचर होगा, जिसे कल्याणी राफेल अडवांसड सिस्टम (केआरएसएस) का नाम दिया गया है।

क्या है

1. हैदराबाद में इस बाबत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। जॉइंट वेंचर के तहत राफेल की हवा से जमीन में मार करने वाले मिसाइल की भी मैनुफैक्चरिंग की जाएगी।
2. दोनों कंपनियों के टॉप अधिकारियों ने बताया कि वे SPICE मिसाइलों की सप्लाई के लिए इंडियन एयर फोर्स से बातचीत कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जॉइंट वेंचर जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना को आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे हाई-टेक एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया कराएगा।
3. यह जॉइंट वेंचर फरवरी 2015 में बनाया गया था लेकिन मैनुफैक्चरिंग प्लांट अब खुला है। इसका खुलना इस लिहाज से अहम है कि यह इस महीने के शुरू में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के बाद हुआ है।
4. इस जॉइंट वेंचर पर काम भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सेना अपनी इफैट्री गाड़ियों के लिए सेकेंड जेनरेशन एटीजीएम का इस्तेमाल कर रही है।
5. इनमें बीएमपी, फगोट, मिलान आदि शामिल हैं। फगोट एटीजीएम को हटाया जा चुका है और भारत में मिलान का प्रॉडक्शन भी रोक दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सैनिकों के पास सिर्फ मिलान एटीजीएम और कोंकुर बचे हुए हैं। इस बीच, सेना थर्ड जेनरेशन एटीजीएम हासिल करने की तैयारी में है।
6. कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा कल्याणी के मुताबिक, सेना के लिए एटीजीएम हासिल करने की खातिर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन (आरएफआई) और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) 2010 से ही दिया जा रहा है।
7. सेना का ऑर्डर 8,000 एटीजीएम के लिए है जिसकी लागत 1 अरब डॉलर होगी। राफेल ने फोर्थ जेनरेशन स्पाइस एटीजीएम की पेशकश की थी लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस खरीद को स्थगित कर दिया।
8. दरअसल, इसे सिंगल वेंडर के जरिए बनाया जाना था जिसे भारत की डिफेंस प्रक्योरमेंट पॉलिसी के तहत प्रोत्साहित किया जाता है।

रूहानी ने फिर संभाली ईरान के राष्ट्रपति की कमान

अमेरिका के साथ गंभीर तनाव के बीच हसन रूहानी ने औपचारिक तौर पर दोबारा ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। उन्होंने ऐतिहासिक परमाणु करार को खत्म करने के खिलाफ ट्रंप सरकार को आगाह भी किया। अमेरिकी संसद कांग्रेस ने हाल में ही ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को प्रचंड बहुमत से पारित किया है।

क्या है

1. रूहानी ने शपथ लेने से पहले यूरोपीय संघ के विदेश नीति मामलों के प्रमुख फेडेरिका मोघरिनी से मुलाकात की।
2. ईरानी राष्ट्रपति ने ईयू प्रतिनिधि से वर्ष 2015 के परमाणु करार को बचाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयास करने को कहा।
3. उन्होंने खचाखच भरे संसदीय कक्ष में कहा, 'ईरान परमाणु करार का पहले उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन, अमेरिका द्वारा पूर्व में की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करने की स्थिति में तेहरान चुप भी नहीं रहेगा।
4. ईरान सम्मान के बदले सम्मान देने की भावना साबित कर चुका है। हमारा देश प्रतिबंध और खतरे का जवाब माकूल तरीके से वाजिब प्रतिरोध के साथ देगा।'
5. समारोह में जिंबाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने शिरकत की, लेकिन कतर के अमीर अनुपस्थित रहे। वर्ष 2013 के शपथ ग्रहण समारोह में वह मौजूद थे।

फेसबुक प्रति कर्मचारी लाभ के मामले में सबसे आगे

फेसबुक ने साल 2017 की दूसरी तिमाही में प्रति कर्मचारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के मामले में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट को पीछे छोड़ दिया है, जबकि ट्विटर को भारी नुकसान हुआ है। यह खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आया है।

क्या है

1. इस रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, जिसने बीती तिमाही के दौरान करीब 20,658 लोगों को रोजगार दिया था, यह बीते वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 43 फीसद का उछाल था, ने प्रति कर्मचारी 188,498 डॉलर का लाभ कमाया है।
2. वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने 52,400 डॉलर और अल्फाबेट ने 46,610 डॉलर प्रति कर्मचारी का लाभ कमाया है। इस दोनों का यह लाभ 30 जून को खत्म हुई तिमाही के दौरान फेसबुक के मुकाबले लगभग चार गुना कम है।
3. इसके बाद वेरिजॉन, एटीएंडटी और फोर्ड का नंबर आता है जिन्होंने प्रतिकर्मचारी क्रमशः 27,405 डॉलर, 15,410 डॉलर और 10,098 डॉलर का लाभ कमाया है।
4. वहीं इस मामले में ट्विटर का हाल काफी बुरा रहा। ट्विटर को बीती तिमाही के दौरान 116 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उसने 36,000 डॉलर प्रति कर्मचारी गंवाए हैं।
5. फेसबुक की दक्षता का कारण यह है कि सॉफ्टवेयर उत्पादों के उत्पादन और वितरण प्रक्रिया के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं होती है।
6. इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बेशक, यहां तक कि मनुष्य को सौंपी जाने वाली नौकरियां भी रोबोट के दायरे में आ रही हैं और अन्य उद्योगों में इस तरह का एकीकरण देखा जा सकता है।

भारत के डाटा सुरक्षा कानून से स्विट्जरलैंड संतुष्ट

स्विट्जरलैंड को लगता है कि भारत के साथ स्वतः सूचना आदान-प्रदान समझौता (आटोमैटिक एक्सचेंज आफ इन्फॉर्मेशन पैक्ट) के लिए उसका डाटा सिव्यूरिटी सिस्टम और गोपनीयता कानून पर्याप्त हैं। उल्लेखनीय है कि इस समझौते के बाद भारत की पहुंच स्विस् बैंकों में जमा कथित कालेधन की जानकारी तक नियमित आधार पर हो जाएगी। स्विस् बैंक भारतीयों के बैंक अकाउंट की डिटेल् सरकार के साथ साझा कर सकती है। इस ऑटोमैटिक इनफॉर्मेशन समझौते के बाद कालाधन को लेकर जानकारी भारत सरकार तक पहुंचाने का रास्ता खुल जाएगा।

क्या है

1. स्विट्जरलैंड सरकार ने अपने राजकीय गजट में इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना और तथ्य प्रकाशित किए हैं।
2. स्विट्स सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ वित्तीय खातों की जानकारी के लिए आटोमैटिक एक्सचेंज आफ इन्फॉर्मेशन पैक्ट करने जा रही है। उसने अन्य वित्तीय केंद्र लिंग्स्टाइन और बहमास का उदाहरण दिया है जो इसी तरह का समझौता करेंगे।
3. सरकार ने यह जानकारी जर्मन भाषा में प्रकाशित की है और साथ ही भारतीय बाजार में अपनी संभावनाएं तलाशने के बारे में भी उसने इसमें बात की है, जिसमें कहा गया है कि स्विट्जरलैंड बीमा और दूसरे वित्तीय सेवाओं सहित भारतीय बाजार में अधिक पहुंच बनाने की संभावना तलाश रहा है। स्विट्स फेडरल काउंसिल ने भारत के साथ इस समझौते की पुष्टि की थी। यह काउंसिल यूरोपीय देशों की शीर्ष गवर्निंग इकाई है।
4. स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को इस साल जून में मंजूरी दे दी थी। उसने कालेधन की सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के लिए गोपनीयता की शर्त रखी है।

घरेलू हिंसा के मामले में टॉप पर है पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा के मामलों में बेतहाशा बढ़ती देखने को मिली है। नैशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो से मिले आंकड़े यही बता रहे हैं। साल 2016 की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू हिंसा के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। 2015 में जहां राज्य में 20,265 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुईं, वहीं 2016 में यह आंकड़ा 34,205 तक पहुंच गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सूबे में घरेलू हिंसा के मामले कितने बढ़ गए हैं।

क्या है

1. आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में भी पिछले साल घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन, पश्चिम बंगाल अब्वल रहा और यूपी दूसरे स्थान पर बना रहा। हालांकि, इस मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। NCRB में फाइनल रिपोर्ट छप जाने के बाद असल आंकड़ों का पता चलेगा, लेकिन इन आंकड़ों से ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा।
2. साल 2015 में पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा के मामलों में 21, 619 गिरफ्तारियां हुईं और पत्नी को पीटने, दहेज की मांग और सूझसाइड के लिए उकसाने के मामले सामने आते रहे।

सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज दीपक मिश्रा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) नियुक्त कर दिया गया। कानून मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि दीपक मिश्रा (63) की नियुक्ति की घोषणा की गई है। वह मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की जगह लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल करीब 14 महीने का होगा।

क्या है

1. जस्टिस दीपक मिश्रा देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वह ओडिशा हाई कोर्ट के तीसरे न्यायमूर्ति होंगे।
2. उनसे पहले ओडिशा से संबंध रखने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जीबी पटनायक भी इस पद को संभाल चुके हैं।
3. जस्टिस दीपक मिश्रा को याकूब मेनन पर दिए गए फैसले पर काफी सुर्खियां मिली थीं। याकूब मेनन की फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया था।
4. वह पटना और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं।

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ

भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हालांकि, आंदोलन की शुरुआत एक दिन पहले यानि की आठ अगस्त 1942 को हुई थी। इस दिन बंबई (अब मुंबई) के एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस

महासमिति ने प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ही 'भारत छोड़ो आंदोलन' बना। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत के फौरन बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और प्रदर्शनों के जरिए से आंदोलन को देशव्यापी बनाया।

इस आंदोलन से जुड़ी खास बातें

1. **बंबई के गोवलिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन** की शुरुआत के समय महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया था। अपनी स्पीच में गांधीजी ने लोगों को एक नारा दिया था। यह 'नारा करो या मरो' था।
2. आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा।
3. भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद बड़ी संख्या में युवा आंदोलन से जुड़े। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल जाने का रास्ता अपनाया। आंदोलन में लाखों की संख्या में आम लोग शामिल हुए।
4. सरकारी आंकाड़ों के अनुसार, **इस जनान्दोलन में 940 लोग मारे गए थे।** इसके अलावा साठ हजार से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, आंदोलन के दौरान 1630 घायल भी हुए थे।
5. ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन।
6. भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन को लोगों का काफी सहयोग मिला।
7. भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी यह आंदोलन तेज गति से चलता रहा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन बना।

विश्व जैव ईंधन दिवस 2017

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस 2017 मनाया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि विश्व जैव ईंधन दिवस का उद्देश्य युवाओं (विद्यालय तथा कॉलेजों में जाने वाले विद्यार्थियों) किसानों तथा अन्य हितधारकों को जैवईंधन के लाभों के प्रति संवेदनशील बनाया तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जैव ईंधन कार्यक्रम में उन्हें शामिल करना है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रयास जन अभियान के तहत किए जाने चाहिए।

क्या है

1. जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि **जैव ईंधन कार्यक्रम के बारे में जागृति पैदा करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 100 जिलों में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाएगा।** यह जागरूकता अभियान जैव ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों की भागीदारी से 11 अगस्त से 14 अगस्त 2017 के बीच चलाया गया।
2. देश में परिवहन तथा घरेलू उपयोग की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए **80 प्रतिशत तेल आयात की आवश्यकता है।** माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक तेल आयातों में 10 प्रतिशत की कमी करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
3. जैवईंधनों के प्रयोग पर रोड मैप बनाने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जैव ईंधनों को बढ़ावा देने से नौकरियाँ बढ़ेंगी, आर्थिक विकास होगा, किसानों को मदद मिलेगी तथा देश में ऊर्जा संकट से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी।
4. **मंत्रालय शीघ्र ही जैव ईंधन नीति लाएगा।** नीति में सरकार की भूमिका निवेश से प्राप्ति, न्यूनतम गारन्टी आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। हाल ही में, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जैवईंधन नीति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री ने कहा कि दोनों नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैव ईंधन के अधिक प्रयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
5. **पूरे देश में दूसरी पीढ़ी के (2जी) जैवईंधन शोधक कारखानों के अनुसंधान तथा अभिकल्प के लिए सरकारी कम्पनियों द्वारा लगभग 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया जा रहा है।** शहरी तथा ग्रामीण अवशेष को ईंधन में बदलने की, बेकार बंजर भूमि को 2जी जैविक ईंधन के लिए कच्चे माल की खेती के उपयुक्त

- बनाने की युक्तियां तलाशी जा रही हैं। मंत्री जी ने बताया कि भारत में जैविक ईंधन की क्षमता अगले 1 से 2 वर्ष में 1 लाख करोड़ के आसपास होगी।
6. **सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देते हुए इसे कम खर्चीला, पर्यावरण अनुकूल परम्परागत ईंधनों का पर्याय बताया।** उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के अलावा कृषि अवशेष, बांस जैसे पौधों, अखाद्य तेल बीजों या शहरी अवशेष द्वारा देशी रूप में तैयार जैव ईंधन से देश के भारी आयात को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे रोजगार बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर तथा देश की बंजर भूमि सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। इस संबंध में श्री गडकरी ने बताया कि जैव ईंधन नीति देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगी।
 7. श्री गडकरी ने यह भी घोषणा की कि वह वित्त मंत्री से बायो डीजल पर जीएसटी मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने को कहेंगे।
 8. **परिवहन क्षेत्र के बारे में बात करते हुए मंत्री ने बताया कि देश में वाहन वृद्धि अरक्षणिय 22 प्रतिशत है।** इसलिए सस्ते तथा हरित जैव ईंधनों तथा बिजली पर आधारित जन परिवहन बढ़ाने के बड़े पैमाने पर प्रयास किये जा रहे हैं।
 9. भारत ने फ्लैक्सी इंजनों के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं। नागपुर शहर में 55 बसें शत-प्रतिशत बायो ईथनॉल से तथा अन्य 50 बसें गंदे नाले के पानी से बने मिथेन से तैयार की गई जैव सीएनजी पर चल रही हैं। यह विद्युत चालित 200 टैक्सी और वाहनों के बेड़े के अलावा है। जहाजरानी तथा अंतर्देशीय जलमार्ग भी जहाज और नौकाओं को मैथनॉल से चलाने की तैयारी में हैं।

विश्व हाथी दिवस-2017

विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है इसका प्रमुख उद्देश्य हाथियों का संरक्षण है। 'विश्व हाथी दिवस' जंगली हाथियों की संख्या, उनकी बेहतरी और प्रबन्धन के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। **आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन हाथी, 'कमजोर हाथी' एवं एशियन हाथी 'लुप्त प्राय' श्रेणी में दिखाए गए हैं।** हाथियों की जनसंख्या के बारे में प्राप्त आकलन के अनुसार दुनियां भर में 400,000 अफ्रीकन हाथी और 40,000 एशियन हाथी है।

क्या है

1. विश्व हाथी दिवस हाथियों के संरक्षण, गैर-कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने, हाथियों के बेहतर इलाज और पकड़े गए हाथियों को अभयारण्यों में भेजे जाने के लिए जागरूकता प्रदान करने की दिशा में कार्य के लिए प्रेरित करता है।
2. **हाथी भारतीय विरासत का प्रमुख भाग है** भारत सरकार इस दिन को हाथियों के प्रति जागरूकता और इनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए मनाती है यद्यपि हाथियों की राष्ट्रव्यापी जनगणना हर पाँच वर्ष में की जाती है लेकिन इस वर्ष यह जनगणना एक वर्ष पूर्व ही की गई है।
3. विश्व हाथी दिवस की शुरुआत कनाडा की फिल्म निर्माता पेक्ट्रीका सिम्स और केनाजवेस्ट पिक्चर्स के श्री माइकल क्लार्क, थाइलैण्ड के एलिफेन्ट री इन्ट्रोडक्शन फाउंडेशन के महासचिव सिवापॉर्न दरदारेन्डा द्वारा 2011 में की गई थी।
4. आधिकारिक रूप से इसका शुभारम्भ 12 अगस्त, 2012 को सुश्री सिम्स और एलिफेन्ट री इन्ट्रोडक्शन फाउंडेशन ने किया था। आज दुनियां के 65 से भी अधिक वन्य जीव संगठन, कई व्यक्ति और बहुत से देश इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं।
5. केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 अगस्त को 'गज यात्रा' का उद्घाटन किया। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 'गज यात्रा' का मूल उद्देश्य है। यह अभियान हाथियों की बहुलता वाले 12 राज्यों में चलाया जाएगा।
6. पर्यावरण मन्त्री ने हाथियों पर अखिल भारतीय जन-गणना 2017 जारी की। राइट ऑफ पेसेज दस्तावेज भी जारी किया गया। यह दस्तावेज भारत में हाथियों के कोरिडोर के बारे में जानकारी मुहैया करता है। सन् 2012 से

2017 के बीच उठाए गए संसदीय प्रश्नोत्तर पर आधारित एक संकलन एनविस सेन्टर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया प्रोजेक्ट एलिफेन्ट डिविजन एवं मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया है।

7. इसका शीर्षक 'ग्लिम्पसिस ऑफ़ इनीशिएटिव टेकन फोर एलिफेन्ट कन्जर्वेशन इन इण्डिया' (भारत में गज संरक्षण के प्रयासों की झलक) है। इस संकलन में पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है यह कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में उपलब्ध कराई गई है। वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य व्यक्तियों को इस डिस्क के जरिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बाद में डॉ. हर्षवर्धन ने इस अवसर पर मौजूद बच्चों को हाथियों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

नॉर्वे में सबसे तेज गति की इंटरनेट सेवा

मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के मामले में महज 13 महीने के भीतर नॉर्वे ने दुनिया के बाकी देशों को पीछे छोड़ दिया है। ब्रॉडबैंड टेस्टिंग के मामले में दुनिया की प्रमुखतम कंपनी ओकला के ताजा आकलन में नॉर्वे में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 52.6 मेगाबाइट्स प्रति सेकेंड पाई गई है।

क्या है

1. नीदरलैंड्स और हंगरी सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट वाले देशों की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह जानकारी चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दी है।
2. 13 महीने पहले हुए सर्वे में नॉर्वे की इंटरनेट स्पीड दुनिया में 11 स्थान पर थी लेकिन अब वह पहले स्थान पर है। महज एक साल में वहां की इंटरनेट स्पीड में 69 फीसद का इजाफा हुआ है।
3. हालात में यह बदलाव तब आया जब टेलीनोर कंपनी ने अपना नेटवर्क विकसित करके सेवा को बेहतर बनाना शुरू किया। टेलीनोर नॉर्वे में इंटरनेट सेवा देने वाली प्रमुख तीन कंपनियों में शामिल है।
4. जुलाई के अंत में कंपनी की सेवा वाली सेवा में डाउनलोड स्पीड 58.6 मेगाबाइट्स प्रति सेकेंड तक दर्ज की गई।

आजाद भारत का तिरंगा अभी तक सुरक्षित

15 अगस्त 1947 को सेंट जार्ज किले पर फहराया गया तिरंगा आज भी सुरक्षित है। इसे पहली बार 26 जनवरी 2013 को किले के संग्रहालय में लोगों के देखने के लिए रखा गया है। एक अधिकारी का कहना है कि आजादी के बाद फहराए गए तिरंगों में केवल एक मात्र यही झंडा है जो अभी तक सुरक्षित बच सका है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। हालांकि झंडे के कुछ हिस्से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये समय की वजह से हुआ। राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये नायाब धरोहर दुरुस्त रहे।

क्या है

1. संग्रहालय ने झंडे को संरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से बाक्स तैयार कराया था। लकड़ी व शीशे के बने बाक्स में इसे रखा गया है। इसके चारों तरफ सिलिका जेल के छह बाक्स रखे गए हैं।
2. इससे नमी को नियंत्रित किया जा रहा है। जिस हाल में ये रखा है उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए गए हैं। कमरे में रोशनी कितनी हो इसके लिए लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
3. आलम यह है कि झंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए प्राकृतिक रोशनी भी बाक्स पर नहीं पड़ने दी जा रही है। धूल व अन्य प्रतिकूल चीजों को इससे दूर रखा जा रहा है।
4. 12-8 फीट के आकार का यह झंडा 15 अगस्त 1947 को सुबह पांच बजकर पांच मिनट पर फहराया गया। संग्रहालय के पास इसका ब्योरा नहीं है कि इसे किस व्यक्ति ने फहराया था।

प्रोफेसर कैलथ को मारकोनी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

अमेरिका स्थित मारकोनी सोसायटी ने भारत में जन्मे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस कैलथ को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। यह पुरस्कार उन्हें आधुनिक संचार तकनीक में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। कैलथ छठे वैज्ञानिक हैं जिन्हें मारकोनी सोसायटी की तरफ से न्यूजर्सी में तीन अक्टूबर को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान दिया जाएगा।

क्या है

1. 82 वर्षीय कैलथ को 2009 में भारत सरकार ने भी पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1935 में पुणे में जन्मे कैलथ को यह अवार्ड इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने शोधकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन किया।
2. प्रोफेसर कैलथ और उनके शिष्यों के नाम 12 पेटेंट हैं। अपने शोधकार्य को उन्होंने उद्योग में तब्दील किया। वह चार कंपनियों के सह-संस्थापक भी हैं। जिनमें 1980 में स्थापित इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और 1996 में स्थापित न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजीस शामिल हैं।
3. भारत में जन्मे अरुण नेत्रवल्ली (71) को भी मारकोनी सोसायटी एक लाख डॉलर (करीब 65 लाख रुपये) का नकद पुरस्कार देगी। नेत्रवल्ली ने डिजिटल वीडियो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया, जो स्मार्टफोन और टीवी में इस्तेमाल की जा रही है।
4. इस सोसायटी का नाम रेडियो का आविष्कार करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता गुलिमो मारकोनी (1874-1937) के नाम पर रखा गया था।

इसरो वैकल्पिक उपग्रह छोड़ेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) नई घड़ियों से युक्त एक वैकल्पिक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में उपस्थित आईआरएनएसएस-1ए उपग्रह पर लगी तीनों रूबिडीयम परमाणु घड़ियाँ वर्ष 2016 के मध्य में ही विफल हो चुकी हैं।

क्या है

1. इसरो का पंगु हो चुकी आईआरएनएसएस -1ए उपग्रह को प्रतिस्थापित करने के लिये जल्द ही एक दूसरा उपग्रह भेजेगा, जिसमें परमाणु घड़ियाँ लगी होंगी।
2. आईआरएनएसएस-1ए में लगी घड़ियों के खराब हो जाने के कारण उसके द्वारा जो आँकड़े भेजे जा रहे हैं वे सटीक नहीं हैं।
3. आगामी आईआरएनएसएस-1एच उपग्रह को अगस्त के अंत तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
4. आईआरएनएसएस के बेड़े में सात उपग्रह हैं, जिनमें 21 परमाणु घड़ियाँ लगी हुई हैं।
5. इसरो ने सातवीं और आखिरी क्षेत्रीय नेविगेशन अंतरिक्ष यान को 2016 में कक्षा में भेजा था। इस बेड़े का पहला उपग्रह जुलाई 2013 में कक्षा में रखा गया था।

पृथ्वी ओवरशूट दिवस

प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता

है, तब 'पृथ्वी ओवरशूट दिवस' मनाया जाता है। इसका संदर्भ इस बात से है कि पर्यावरणीय दृष्टि से एवं प्राकृतिक संसाधनों की पहुँच की दृष्टि से जितनी मात्रा में मानव को इनका इस्तेमाल करना चाहिये, वस्तुतः मनुष्य उस सीमा को प्राप्त कर चुका है। इसके बाद हम जितनी मात्रा में इन संसाधनों का उपभोग करेंगे, उतना हमारे भविष्य के लिये निर्धारित वार्षिक कोटे से अतिरिक्त का उपभोग होगा। इस वर्ष पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2 अगस्त को मनाया गया।

क्या है

1. अभी तक की अपनी तरह की पहली ऐसी गणना है। ई.ओ.डी. की गणना को वर्ष 1987 से आरंभ किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष मात्र सात महीने में ही हम उस स्तर को पार कर लेते हैं जो वर्ष भर के

आईआरएनएसएस -1ए क्या है ?

1. यह भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली का पहला उपग्रह है।
2. इस प्रणाली में सात उपग्रह हैं।
3. यह भारत और भारत के बाहर लगभग 1500 किलोमीटर तक के दायरे में किसी की अवस्थिति की जानकारी देने के लिये बनाया गया है।

NAViC क्या है?

1. 'नाविक' 1,420 करोड़ रुपए की लागत से सात उपग्रहों से मिलकर बना भारत की अपनी जीपीएस-जैसी प्रणाली है, जिसे व्यक्तियों या वस्तुओं के स्थान और समय के बारे में सटीक जानकारी देने के लिये बनाया गया है।
2. यह अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या रूस के ग्लोनास (GLONASS) जैसी है।

- कोटे के रूप में हमारे लिये निर्धारित किया जाता है। यह गणना वस्तुतः हमारी पर्यावरणीय गिरावट (**environmental degradation**) की दर को प्रदर्शित करती है।
2. ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क (जो कि प्रतिवर्ष ई.ओ.डी. की गणना करता है) के अनुसार, दुनिया के समस्त पारिस्थितिक पदचिह्न (world's ecological footprint) का लगभग 60 प्रतिशत भाग कार्बन उत्सर्जन से बना होता है, जिसे विश्व पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते (Paris climate change agreement) के तहत रोकने की कोशिश की जा रही है।
 3. हालाँकि मात्र इन प्रयासों से अधिक सफलता मिल पाना संभव नहीं है, इसके लिये और अधिक बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम वर्तमान के कार्बन उत्सर्जन की दर को सीधा इसके अर्द्ध स्तर पर ले आते हैं, तब भी हम ई.ओ.डी. में मात्र 89 दिन या तीन महीनों की ही वृद्धि कर सकते हैं।
 4. इसके बावजूद हम दो महीने के घाटे की स्थिति में रहेंगे। स्पष्ट है कि इस दिशा में और अधिक गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।